



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

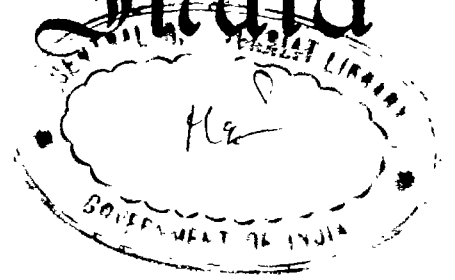
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 447]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2000/भाद्र 7, 1922

No. 447]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2000/BHADRA 7, 1922

दिल्ली विकास प्राधिकरण

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2000

सा.का.नि. 683(अ).—सामान्य सेवा विनियम जी.एस.आर. 624(अ), भारत के असाधारण राजपत्र में भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना सं. 7(11)96 पी.बी.-1/पी.एंड सी. (पी.) दिनांक 8-9-99 इस संबंध में विभिन्न दि.वि.प्रा. आचरण, अनुशासनात्मक एवं अपील विनियम 1999 विधिवत् संशोधित किए गए।

विनियम सं.

21 (3) निर्वाह भत्ता

यदि किसी कर्मचारी को आपराधिक आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसे जमानत नहीं मिलती है तो ऐसे कर्मचारी को कोई निर्वाह भत्ता देय नहीं है। जमानत मिलने पर, यदि सक्षम प्राधिकारी निलम्बन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं तो कर्मचारी जमानत मिलने की तारीख से निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

22 (क) निलम्बन अवधि के संबंध में कार्रवाई

यदि कोई कर्मचारी निर्दोष घोषित किया जाता है और उसे विनियम 23 में वर्णित कोई दण्ड नहीं दिया जाता है तो उसे उस पूर्ण वेतन और भत्तों जो यदि वह निलम्बित नहीं होता तो पाने का हकदार होता, में से उसे पहले दिया गया निर्वाह भत्ता घटा कर दिया जाएगा।

किया जाने वाला संशोधन

यदि किसी कर्मचारी को आपराधिक आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसे जमानत नहीं मिलती है तो ऐसे कर्मचारी को पैरा 21(1) में वर्णित निर्वाह भत्ता देय है। जमानत मिलने पर, यदि सक्षम प्राधिकारी निलम्बन को जारी रखने का निर्णय लेते हैं तो कर्मचारी निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

23 (9) : स्पष्टीकरण

जिस मामले में निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई मामूली दण्ड लगाने के निर्णय के साथ समाप्त हुई हो अथवा कोई अन्य जांच किए बिना निलम्बन रद्द कर दिया गया हो अथवा यदि कर्मचारी निर्दोष घोषित किया जाता है और उसे विनियम 23 में वर्णित दण्ड में से कोई दण्ड नहीं दिया जाता है तो एफ. आर. 54(बी) के निबंधनों के अनुसार निलम्बन को पूर्ण रूप से गैर-न्यायोचित माना जाएगा और इसलिए संबंधित कर्मचारी को एफ.आर. 54(बी) के अंतर्गत उपयुक्त आदेश जारी करके उन्हें निलम्बन अवधि के लिए पूर्ण वेतन एवं भत्ते दिए जाने चाहिए। (कर्मचारी को वह पूरा वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे जो यदि वह निलम्बित नहीं होता तो पाने का हकदार होता।)

[फा. सं. 7(11)96/पीआर-1/पी एण्ड सी (पी.)]

विश्व मोहन जैसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 29th August, 2000

G.S.R. 683(E).—G.S.R. 624(E), the notification No. 7(11)96-PB-I/P&C(P) dated 8-9-99 published under Part-II, Section 3, Sub-section (i) in the Extraordinary Gazette of India. In this connection various DDA, Conduct, Disciplinary & Appeal Regulations, 1999 duly corrected.

Regulation No.**21(3): Subsistence Allowance.**

If any employee is arrested by the police on a criminal charge and bail is not granted, no subsistence allowance is payable. On grant of bail if the competent authority decides to continue the suspension, the employee shall be entitled to subsistence allowance from the date he is granted bail.

22 (a): Treatment of the period of suspension.

If the employee is exonerated and not awarded any of the penalties mentioned in Regulation 23, the full pay and allowances which he would have been entitled to if he had not been suspended, less the subsistence allowance already paid to him.

Modification to be made

If any employee is arrested by the police on a criminal charge and bail is not granted, subsistence allowance as mentioned in para 21(1) is payable. On grant of bail if the competent authority decides to continue the suspension, the employee shall be entitled to subsistence allowance.

23 (ix): Explanation.

Where departmental proceedings against a suspended employee finally end with the imposition of minor penalty, or when suspension is revoked without holding any further inquiry or if the employee is exonerated and not awarded any of the penalties mentioned in Regulation 23, the suspension can be said to be wholly unjustified in the terms of F.R. 54(B) and the employee concerned should, therefore, be paid full pay and allowances for the period of suspension by passing suitable orders under F.R. 54(B). The employee shall be paid full pay and allowances to which he would have been entitled, had he not been suspended.

[F. No. 7(11)96/PR-I/P&CC(P)]

V.M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.